एक स्पष्ट संकेत

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

29 अक्टूबर, 2021

भले ही भारत और चीन बातचीत में शामिल हों, लेकिन तनाव की वर्तमान स्थिति जारी रहने की संभावना है।

भारत के साथ बातचीत में जारी गतिरोध के बीच एक नया सीमा कानून पारित करने वाले चीन ने नई दिल्ली को एक स्पष्ट संकेत भेजा है कि बीजिंग एलएसी के साथ 18 महीने लंबे संकट को जल्दी से समाप्त करने के मूड में नहीं है। सीमा कानून, जो 1 जनवरी से प्रभावी होगा, चीन में विभिन्न एजेंसियों की जिम्मेदारियों को सेना से लेकर स्थानीय अधिकारियों तक, सीमाओं की रक्षा में निर्दिष्ट करता है। यह कानून "निर्धारित करता है कि चीन के जनवादी गणराज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पवित्र और अहिंसक है"। सेना को "प्रादेशिक संप्रभुता और भूमि सीमाओं को कमजोर करने वाले किसी भी कार्य के खिलाफ सुरक्षा और मुकाबला करने" का आह्वान करते हुए, कानून कहता है कि चीनी सेना "सीमा कर्तव्यों का पालन करेगी" आक्रमण, अतिक्रमण, उकसावे और अन्य कृत्यों को रोकने और मुकाबला करने के लिए।

"भारत ने चीन से यह कहते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि उसे एलएसी को एकतरफा रूप से बदलने के लिए पिछले साल से पीएलए की कार्यवाहियों को औपचारिक रूप देने के लिए "बहाने" के रूप में कानून का उपयोग नहीं करना चाहिए। जबकि कानून कहता है कि बीजिंग अपनी सीमाओं को तय करने के लिए अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत करेगा, भारत ने चीन को याद दिलाया कि कानून का भारत-चीन सीमा पर बहुत कम असर पड़ेगा क्योंकि दोनों पक्षों ने अभी तक सीमा प्रश्न को हल नहीं किया है। भारत की चिंताओं के जवाब में, चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि कानून मौजूदा समझौतों के कार्यान्वयन को प्रभावित नहीं करेगा। इस कानून के केवल दूसरे देश के लिए भी निहितार्थ हैं, चीन की अनसुलझी भूमि सीमाएँ हैं - भूटान - सीमावर्ती क्षेत्रों को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान करता है। उन प्रयासों में विवादित क्षेत्रों सहित सीमांत गांवों का निर्माण जारी है।

चीनी पक्ष भारत के अनुच्छेद-370 को निरस्त करने और लद्दाख में एक केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण के लिए एक "आंतरिक" मामले के रूप में कानून को सही ठहरा सकता है, जिसका चीन ने कड़ा विरोध किया क्योंकि इसमें अक्साई चिन शामिल था, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर है।

मार्च में पहली बार प्रस्तावित नया चीनी कानून एलएसी संकट में लगभग एक साल बाद आया। इसने पिछले चार सीमा समझौतों के उल्लंघन में, 2020 की गर्मियों में आगे के क्षेत्रों में सैनिकों के दो डिवीजनों के पीएलए के एकत्रीकरण का पालन किया, और अनिवार्य रूप से उन चालों को मंजूरी पर मुहर लगा देता है। यदि नई दिल्ली और बीजिंग दोनों कम से कम इस बात पर सहमत प्रतीत होते हैं कि कानून पिछले समझौतों को प्रभावित नहीं करेगा, तो तथ्य यह है कि वे समझौते पहले से ही खस्ताहाल हैं।

10 अक्टूबर को आयोजित एलएसी वार्ता का अंतिम दौर दोनों पक्षों के व्यापारिक आरोपों के साथ समाप्त हुआ, बीजिंग ने "अवास्तविक" मांग करने के लिए भारत को दोषी ठहराया और नई दिल्ली ने जवाब दिया कि दूसरे पक्ष ने समाधान के लिए कोई वास्तविक प्रस्ताव नहीं दिया।

दरअसल, नया कानून इस बात को रेखांकित करता है कि जहाँ तक उसकी सीमाओं का संबंध है, चीन को समझौता करने के लिए बहुत कम जगह दिखाई दे रही है। भले ही भारत और चीन बातचीत जारी रखते हैं, कानून नवीनतम संकेत है कि सीमा पर वर्तमान स्थिति, दोनों पक्षों द्वारा अग्रिम क्षेत्रों में निरंतर तैनाती और बुनियादी ढांचे के निर्माण द्वारा चिह्नित, लंबी अवधि तक जारी रहने की संभावना है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. हाल ही में किस देश ने सीमा कानून पारित किया है?

(a) चीन

(b) भूटान

(c) नेपाल

(d) रूस

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Which country has recently passed the border law?

(a) China

(b) Bhutan

(c) Nepal

(d) Russia

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. चीन का नवीन सीमा कानून क्या है? यह किस प्रकार से अपने पड़ोसी देशों से सीमा समझौता करने की बात करता है? और भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है? (250 शब्द)

Q. What is China's new border law? How does it talk about negotiating a border agreement with its neighboring countries? And What effect can it have on India? (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।